डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 16 अक्टूबर, 2025, डिस्पेच दिनांक 16 अक्टूबर, 2025

| वर्ष 69 | अंक 10 | भोपाल | 16 अक्टूबर, 2025 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को दी 42 हजार करोड़ की ऐतिहासिक सौगात

'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' और 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' से खुलेगा समृद्धि का नया अध्याय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना" और "दलहन आत्मनिर्भरता मिशन" का शुभारंभ

कृषि क्षेत्र, पशुपालन, मत्स्यपालन, एफपीओ एवं इनोवेशन में मिली 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की ऐतिहासिक सौगात

प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1,100 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया

42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण सौगातें देने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों की ओर से जताया आभार

पूसा, दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी भी हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह व रामनाथ ठाकुर सहित कई मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि लाखों किसानों सहित विभिन्न स्थानों से वर्चुअल हुए सम्मिलित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दलहन उत्पादक, एआईएफ और पशुपालन, मत्स्य पालन से जुड़े किसानों से पूसा परिसर में किया सीधा संवाद

कार्यक्रम में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख जी की जयंती के अवसर पर किया उनका स्मरण

प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और तकनीकी नवाचारों वाले किसानों को किया सम्मानित

जीएसटी की दरें घटाने से कृषि यंत्र सस्ते होने और एमएसपी बढ़ाने पर केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का माना आभार

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने यूरिया के बढ़े भाव का बोझ किसानों पर नहीं आने दिया- श्री शिवराज सिंह

संस्थागत ऋण, फसल बीमा जैसी अनेक योजनाओं से किसानों को लगातार मिली हैं मदद- श्री शिवराज सिंह

दालों में आत्मनिर्भरता के लिए दलहन मिशन और जिलों के अंत्योदय हेतु प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का शुभारंभ ऐतिहासिक पहल- श्री शिवराज सिंह

प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और विजन के कारण देश के किसानों का हो रहा हैं कल्याण-श्री शिवराज सिंह

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे- केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह

दिल्ली | दिल्ली के पूसा में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बहुमूल्य सौगातें दी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी भी प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी ने दलहन उत्पादक, एग्रीकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) और पशुपालन व मत्स्य पालन से जुड़े किसानों के विभिन्न समूहों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं व नवाचारों पर गहन चर्चा की। महान समाजसेवी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख जी की जयंती पर उनका स्मरण भी किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ ऐतिहासिक पहल हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो महत्वपूर्ण योजनाओं— "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना" और "दलहन आत्मनिर्भरता मिशन" — का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना देश के आकांक्षी जिलों में कृषि उत्थान के लिए 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाओं को समन्वित करते हुए लॉन्च की गई है, वहीं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को दालों के बढ़ते उपभोग को ध्यान में रखते हुए, देश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु शुरू किया गया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।

प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1,100 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इन सब परियोजनाओं के माध्यम से देश को 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की निवेश सौगात मिली, जिससे ग्रामीण भारत में अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स और वेयरहाउस जैसी सुविधाएं स्थापित होंगी।

किसानों एवं एफपीओ का सम्मान

प्रधानमंत्री ने देशभर के उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और तकनीकी नवाचारों वाले किसानों को सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों को सामाजिक मान्यता भी दी।

यूरिया एवं डीएपी की कीमतें स्थिर, जीएसटी में राहत

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने यूरिया के बढ़े भाव का बोझ किसानों पर नहीं आने दिया। यूरिया की एक बोरी सिर्फ रुपये 266 में उपलब्ध है और डीएपी की बोरी रुपये 1,350 में उपलब्ध है, जिसमें सरकार भारी सब्सिडी जारी कर रही है। श्री शिवराज सिंह ने यह भी कहा कि कृषि यंत्रों पर जीएसटी घटाकर किसानों को आसान और सस्ता विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। गेहूं पर रुपये 160 प्रति क्विंटल, चना पर रुपये 200+ प्रति क्विंटल, मसूर पर रुपये 300 प्रति क्विंटल, सरसों पर रुपये 250 प्रति क्विंटल, कुसुम पर रुपये 600 प्रति क्विंटल।

संस्थागत ऋण, बीमा और किसानों का वित्तीय सशक्तिकरण

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक रुपये 3.90 लाख करोड़ सीधे किसानों के खातों में पहुंचे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वर्ष 2024-25 में रुपये 10 लाख करोड़ से अधिक के ऋण और रुपये 1.62 लाख करोड़ ब्याज सब्सिडी दी गई है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने चलाया गया "दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान"

प्रमुख सचिव ने की अभियान के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को दोगुना से अधिक करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश में निरंतर गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत गांव गांव में घर-घर जाकर पशुपालकों को पशुओं में नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं के टीकाकरण, उनकी स्वास्थ्य रक्षा, संतुलित पशु आहार, पशु पोषण आदि के बारे में तकनीकी और व्यावहारिक जानकारी दी गई। पशुपालकों को उपलब्ध संसाधनों में कम खर्च पर अधिक दूध उत्पादन करने और ज्यादा लाभ कमाने के बारे में जागरूक किया गया।

प्रमुख सचिव, पशुपालन एवं डेयरी श्री उमाकांत उमराव द्वारा पशुपालन संचालनालय में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के प्रथम चरण के पूर्ण होने पर अभियान के अंतर्गत की गई कार्यवाही एवं मैदानी स्तर पर किए गए विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव ने प्रथम चरण में प्राप्त विभिन्न प्रकार के सुझावों पर क्रियान्वयन और द्वितीय चरण की तैयारी के संबंध में आवश्यक निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए.

बैठक में बताया गया कि अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत विभाग के अधिकारी–कर्मचारियों द्वारा 10 या अधिक गौवंश–भैंस वंश पालने वाले पशुपालकों से संवाद करने के लक्ष्य अनुसार समस्त जिलों में लगभग 370000 पशुपालकों से उनके घर पहुंचकर भेंट की और उन्हें पशुपालन के संबंध में जानकारी दी, साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया। अभियान के दौरान मुख्य फोकस पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने पर रहा।

अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, संभागीय आयुक्त, जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों और समाज के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर पशुपालकों से भेंट की गई और उन्हें दूध उत्पादन और पशुपालन से ज्यादा लाभ उठाने के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई एवं पशुपालकों के अनुभव भी साझा किए गए। किसानों और पशुपालकों ने भी उत्साहपूर्वक इस अभियान में सहभागिता की। बैठक में डॉ. उमेश चंद्र शर्मा प्रेसिडेंट वेटरनरी कौंसिल ऑफ़ इंडिया न्यू दिल्ली, संचालक पशुपालन डॉ. पी.एस. पटेल, डॉ. अनुपम अग्रवाल, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल के प्रबंध संचालक डॉ. सत्यनिधि शुक्ला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. प्रवीण शिंदे एवं जिलों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

हर एक किसान के साथ खड़ी है सरकार, एक-एक खेत का किया जा रहा है सर्वे

133 करोड 80 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ है, आपदा ग्रस्त प्रत्येक किसान को मदद दी जाएगी। विपत्ति में आए हर एक किसान को राहत राशि मिलेगी और एक-एक खेत का सर्वे किया गया है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना का लाभ भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 133 करोड 80 लाख रुपए

की लागत के निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया। इनमें 127. 63 करोड रुपए लागत के 23 किलोमीटर से अधिक लंबाई के इंगोरिया से उन्हेल टू लेन मार्ग निर्माण का भूमि-पूजन सम्मिलित है। साथ ही 1.26 करोड़ के नवीन नगर परिषद कार्यालय भवन निर्माण एवं 2.17 करोड़ के चिड़ी से रावदिया मार्ग निर्माण का भूमि पूजन तथा 2.74 करोड रुपए के करनावद विद्युत उपकेंद्र निर्माण का लोकार्पण भी किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उन्हेल क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जिनमें उन्हेल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन, रामगढ़ बिहारिया मार्ग पर नारायण धाम को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण तथा उन्हेल में विश्रामगृह का निर्माण सम्मिलित है। उन्हेल में इमली तथा मावा उद्योग से जुड़े हुए व्यक्तियों एवं उनके व्यापार विकास के लिए भी कार्य किया जाएगा।

राज्य शासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों के हित में भावांतर योजना लागू की गई है। किसानों को घर बैठे योजना का लाभ दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसलों के मामले में प्रभावित किसानों को राहत राशि दी जा रही है। जैसे-जैसे जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट प्राप्त होती जा रही है, वहां के किसानों को राहत राशि का वितरण किया जा रहा है। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। बहनों को लाडली बहना योजना के तहत सहायता राशि दी जा रही है। यह राशि दीपावली के पूर्व उपलब्ध कराएंगे। गोपालन गौशाला योजना अंतर्गत 25 देसी गायों के पालन पर 40 लाख रुपए के प्रोजेक्ट में अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान शासन देगा। प्रदेश में गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास के सराहनीय कार्य लगातार किए जा रहे हैं।

बहुउद्देशीय पैक्स के विस्तार हेतु संभागवार विशेषताओं की समीक्षा के निर्देश

मंत्री श्री सारंग ने की सहकारिता विभाग की समीक्षा

भोपाल :अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के समापन को दृष्टिगत रखते हुए सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंत्रालय में सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की। बैठक में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत की गई गतिविधियों और नवाचारों की समीक्षा की गई और समापन कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर प्रदेश में सहकारी समितियों की गतिविधियों और नवाचारों को जनता के सामने प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समापन समारोह में सहकारी समितियों की भूमिका, उनके द्वारा किए गए नवाचार और समाज को लाभ पहुँचाने वाले उपायों को उजागर किया जाना आवश्यक है, ताकि जनता में सहकारिता के महत्व और प्रभाव का व्यापक संचार हो।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में पैक्स के पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, शादी हॉल, और मैरिज गार्डन सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में सक्रिय होने की संभावना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने और सामूहिक सुदृढ़ता में वृद्धि होने की संभावना है। उन्होंने बहुउद्देश्यीय पैक्स (एम-पैक्स) के विस्तार हेतु संभागवार समीक्षा करने

और हर संभाग की विशेषताओं के अनुसार समिति गठन की संभावनाओं का आकलन करने का निर्देश दिया।

मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि न केवल संभाग में प्रचलित गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए, बल्कि अन्य संभावित व्यावसायिक अवसरों की भी पहचान की जाए। इसके लिए आवश्यक समर्थन और संसाधन विभाग द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त बैठक में मंत्री श्री सारंग ने CPPP (Co-operative Public Private Partnership) के अंतर्गत हुई प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि सीपीपीपी की सफलता सुनिश्चित करने हेतु कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।

सहकारी बैंक की नौकरी सेवा का बेहतर माध्यम है – मंत्री श्री सारंग

मंत्री श्री सारंग ने किया नवनियुक्त अधिकारियों से संवाद ● 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के लिये नवनियुक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण सत्र

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में आईबीपीएस के माध्यम से चयनित प्रदेश के 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के नवनियुक्त अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, प्रबंधक (प्रशासन/लेखा) एवं नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण सत्र का समापन करते हुए कहा कि आप सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान प्रदेश के सहकारी साख आंदोलन से जुड़े जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश के त्रि-स्तरीय सहकारी ढांचे में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यहां अधिकारी के रूप में आपको ईश्वर ने प्रदेश के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों में रहने वाले अंतिम छोर के व्यक्ति की सेवा का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि अपेक्स बैंक द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण के आधार पर यदि आप अपनी ऊर्जा, ज्ञान, कौशल और विवेक के साथ पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो जहां एक ओर आप जरूरतमंद लोगों की बेहतर सेवा कर

पाएंगे, वहीं दूसरी ओर अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण भी कर सकेंगे।

मंत्री श्री सारंग ने श्री शिव खेड़ा, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, गौतम बुद्ध एवं अन्य दार्शनिकों के दृष्टांतों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि कोई भी कार्य नया नहीं होता, लेकिन किसी कार्य को नवाचार और कौशल के साथ संपन्न करना ही उत्कृष्ट कार्यप्रणाली को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जिलों में अच्छे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर आप स्वयं को सोने के समान चमकदार साबित करें।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि पैक्स हमारी आधारशिला हैं, अतः इनकी कार्यप्रणाली का पूर्ण कंप्यूटरीकरण आपकी प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बाद व्यवसाय के विविधीकरण के लक्ष्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पैक्स पर ही जिला बैंकों और अपेक्स बैंक की मजबूती निर्भर करती है।

उन्होंने कहा कि सभी जिला बैंक वर्तमान में क्रेडिट, उर्वरक, उपार्जन एवं पीडीएस का कार्य कर रही हैं, किंतु प्रतिस्पर्धा के इस दौर में स्वयं को अधिक सशक्त बनाने के लिए व्यवसाय के अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। विशेषकर छोटे ऋण, कम ब्याज दरों पर, सरल शर्तों और आवश्यक कार्यालयीन औपचारिकताओं के साथ वितरित किए जाने चाहिए। साथ ही जिले में स्थित 54 विभागों के सभी अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर इस दिशा में कार्य करना होगा।

कार्यक्रम के अंत में मंत्री श्री सारंग ने नवनियुक्त अधिकारियों को अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कॉलेज, भोपाल में आयोजित 12 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करने पर प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

इस अवसर पर अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता, ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य श्री पी.एस. तिवारी, श्री मनोज सिन्हा, श्रीमती अरुणा दुबे, श्री अरुण मिश्र, श्री के.टी. सज्जन, श्री अरविंद बौद्ध, श्री अरुण माथुर सहित अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन के लिए अभी तक 4 लाख 68 हजार 946 किसानों ने कराया पंजीयन

भोपाल : समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए अभी तक 4 लाख 68 हजार 946 किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीयन 10 अक्टूबर तक होगा। पिछले वर्ष 7 लाख 84 हजार 845 किसानों ने पंजीयन कराया था। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि समय पर पंजीयन करा लें जिससे उपार्जन में कोई समस्या नहीं हो। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। प्रदेश में 1255 पंजीयन केन्द्र बनाये गये हैं।

पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर और एम.पी. किसान एप पर भी की गई है।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। प्रति पंजीयन के लिये 50 रूपये से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज़ एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोट पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।

जिलेवार पंजीयन

प्रदेश में हुए कुल पंजीयन में मुख्य रूप से जिला बालाघाट में 57 हजार 223 किसान, जबलपुर में 24 हजार 710, सिवनी में 28 हजार 349, कटनी में 40 हजार 391, मण्डला में 18 हजार 473, डिण्डोरी में 10 हजार 590, नरसिंहपुर में 7 हजार 245, छिंदवाड़ा में 1,468, रीवा में 42 हजार 878, सतना में 36 हजार 113, मैहर में 17 हजार 427, सिंगरौली में 19 हजार 997, सीधी में 18 हजार 305, मऊगंज में 14 हजार 715, शहडोल में 23 हजार 723, उमरिया में 18 हजार 748, अनूपपुर में 13 हजार 612, पन्ना में 20 हजार 204, दमोह में 14 हजार 508, सागर में 889, रायसेन में 7 हजार 340, सीहोर में 5 हजार 434, विदिशा में 484, भोपाल में 33, नर्मदापुरम में 17 हजार 117, बैतूल में 5 हजार 905, हरदा में 315, भिंड में 363, मुरैना में 1533, श्योपुर में 43, ग्वालियर में 202, शिवपुरी में 205, दतिया में 130, देवास में 203, बड़वानी में 41 और झाबुआ में 20 किसानों ने पंजीयन कराया है।

देश का पहला सहकारी CBG प्लांट शुरू, सहकारिता से सशक्त होगा कृषि व ऊर्जा क्षेत्र : अमित शाह

दिल्ली |केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपरगाव में देश के पहले सहकारी मल्टी-फ़ीड कंप्रेस्ड बायोगैस(CBG) प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़णवीस, उप-मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और श्री अजित पवार, केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि भारत के सहकारी चीनी मिलों के इतिहास में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और पोटाश ग्रैन्यूल निर्माण इकाई की शुरुआत पहली बार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाने में हो रही है। उन्होंने कहा कि एक नई शुरुआत के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने वाले दिनों में 15 चयनित चीनी मिलों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की सहायता से दोनों संयंत्र स्थापित करने के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह नई शुरुआत आने वाले दिनों में देशभर के चीनी मिलों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगी।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के किसानों के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि बीते एक अक्टूबर को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' की शुरुआत की, जिसके तहत अगले छह वर्षों में 11,440 करोड़ रुपए का उपयोग दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि यदि अरहर, उड़द और मसूर डाल का उत्पादन करने वाले किसान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) औरभारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF) के साथ पंजीकरण कराते हैं, तो भारत सरकार उनकी पूरी दलहन फसलन्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद लेगी। इससे महाराष्ट्र के किसानों को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि देश के दो करोड़ किसानों से हम शत प्रतिशत एमएसपी पर दलहन खरीदेंगे। इसके अलावा, एक हजार प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी और 88 लाख उच्च गुणवत्ता वाले बीज किट भी वितरित किए जाएँगे।

प्रदेश के गांव-गांव में चल रहा है "दुग्ध समृद्धि संपर्क" अभियान

पशुपालकों को दी जा रही है नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की जानकारी

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को दोगुना से अधिक करने और उसके माध्यम से पशुपालक किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प को पूरा करने के लिये प्रदेश में 'दुग्ध समृद्धि संपर्क' अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत पशुपालन विभाग का अमला गांवों में घर-घर जाकर पशुपालकों से व्यक्तिश: संपर्क कर रहा है और उन्हें पशुओं में नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन दे रहा है। साथ ही पशुपालकों की समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। अभियान का प्रथम चरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को आयोजित हुई ग्राम सभाओं से शुरू हुआ, जो 9 अक्टूबर तक चलेगा।

मंत्री श्री पटेल ने किया दमोह जिले के ग्रामों में पशुपालकों से संपर्क

अभियान के अंतर्गत पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल ने शनिवार को दमोह जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम खिरिया छक्का पहुंचकर पशुपालक किसानों से संपर्क किया और उन्हें दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और नस्ल सुधार आदि की जानकारी दी। मंत्री श्री पटेल ने पशुपालकों के घर पहुंचकर पशुपालन के संबंध में चर्चा की और अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। साथ ही उन्नत पशुपालन विधियां अपना कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये कहा। मंत्री श्री पटेल से चर्चा के दौरान ग्राम के पशुपालक श्री धर्मेंद्र पटेल ने बताया कि उन्होंने नस्ल सुधार के क्षेत्र में कार्य किया है, जिससे दुग्ध उत्पादन में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि यह उल्लेखनीय कार्य है, जो अन्य पशुपालकों के लिए प्रेरणा दायक है। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से आग्रह किया कि इस अभियान से जुड़कर पशुपालन को बढ़ावा दें और लाभ कमाएं।

प्रमुख सचिव पशुपालन ने किया रायसेन एवं विदिशा जिले में संपर्क

दुग्ध समृद्धि अभियान के अंतर्गत प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास श्री उमाकांत उमराव ने रायसेन जिले के ग्राम आमा और पिपलिया चांदखां का भ्रमण किया तथा पशुपालकों से चर्चा कर उन्हें दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की नई तकनीक के संबंध में जानकारी दी। प्रमुख सचिव ने विदिशा जिले के ग्रामों पुरेनिया, पीपलखेड़ा कला, अमरापुरा, बेरखेड़ी, खैरखेड़ी में पहुंचकर पशुपालकों से संवाद कर पशुओं की नस्ल सुधार, खासकर सीमन से बछियां ही जन्मे, दुग्ध उत्पादन में और कैसे वृद्धि हो ताकि दुग्ध की पूर्ति सुगमता से हो और पशुपालकों की आमदनी में इजाफा हो, की जानकारी दी। उन्होंने पशुपालकों से पूछा कि क्या उन्हें शासन की पशुपालन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पशुपालकों ने बताया कि पशुपालन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी गांव आते हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ देते हैं।

प्रमुख सचिव श्री उमराव ने पशु मैत्री श्री शैलेन्द्र भार्गव द्वारा किए जा रहे कार्यो की प्रशंसा की और आगामी 26 जनवरी को उन्हें पुरस्कृत करने के निर्देश कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता को दिये। पशु पालकों को केसीसी जारी करने और पशुओं का बीमा कराने संबंधी निर्देश भी दिये।

प्रमुख सचिव ने दिये अभियान संबंधी निर्देश

प्रमुख सचिव श्री उमराव ने निरीक्षण के दौरान दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के अंतर्गत पशुपालकों से सहज संवाद स्थापित करने और उन्हें शासन की योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ देने के सबंध में विभागीय अमले को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। अभियान के अंतर्गत प्रदेश के पशुपालकों से व्यक्तिगत संवाद स्थापित कर नस्ल सुधार, पशु पोषण एवं पशु स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी साझा करें। संबंधित विषयों पर पशुपालकों से समानुभाव के साथ सहज संवाद स्थापित किया जाना आवश्यक है। मैत्री, सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारी द्वारा ग्राम सम्पर्क से पूर्व उपलब्ध कराई गई सूची (भारत पशुधन एप अनुसार) में उल्लेखित पशुपालकों से दूरभाष पर सम्पर्क कर, पहुंचने की तिथि व समय की सहमति प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं।

सहकारी बैंकिंग में ऐतिहासिक नवाचार: टीजेएसबी बैंक ने डिजिटल यात्रा में लिया बड़ा कदम

ठाणे (महाराष्ट्र): टीजेएसबी सहकारी बैंक ने देश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। यह भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने यूपीआई-आईसीडी (Interoperable Cash Deposit) अधिग्रहक के रूप में लाइव होकर डिजिटल भुगतान और नकद लेनदेन के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है।

इस उपलब्धि से बैंक की अग्रणी भूमिका उजागर होती है, जो सहकारी बैंकिंग में ग्राहक-हितैषी और अभिनव तकनीक को लागू करने में हमेशा अग्रसर रहा है।

यूपीआई-आईसीडी फ्रेमवर्क और महत्व

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा शुरू किया गया यूपीआई-आईसीडी फ्रेमवर्क ग्राहकों को किसी भी भागीदार बैंक की नकद जमा मशीन पर केवल यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके नकद जमा या निकासी करने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में डेबिट कार्ड या बैंक-विशिष्ट प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती। यह इंटरऑपरेबिलिटी नकद सेवाओं तक सुगम, सुरक्षित और समावेशी पहुँच सुनिश्चित करती है।

पर्टो (PERTO) एंड्रॉयड कैश रीसायकलर मशीन

टीजेएसबी बैंक की पर्टो (PERTO) एंड्रॉयड कैश रीसायकलर मशीन को एनपीसीआई द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 (7 से 9 अक्टूबर, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई) में प्रदर्शित किया जा रहा है। यह मशीन यूपीआई एटीएम और यूपीआई इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट दोनों के रूप में कार्य करती है, जिससे किसी भी ICD या ICCDW-सक्षम बैंक का उपयोगकर्ता अपनी पसंदीदा यूपीआई ऐप से नकद लेनदेन सहज रूप से कर सकता है।

इस तकनीक से ग्राहक केवल एक साधारण क्यूआर स्कैन के माध्यम से नकद निकाल या जमा कर सकते हैं, जिससे पारंपरिक एटीएम या कार्ड पर निर्भरता कम होती है और लेनदेन अधिक आसान और सुरक्षित बनता है।

टीजेएसबी बैंक की पहचान और दृष्टिकोण

1972 में स्थापित, टीजेएसबी सहकारी बैंक भारत के अग्रणी बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों में से एक है। इसका मजबूत नेटवर्क महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और नवाचार पर जोर देने के कारण यह बैंक सहकारी बैंकिंग को नई परिभाषा दे रहा है। बैंक का यह कदम यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तनकारी माना जा रहा है, जो डिजिटल सुविधा और नकद लेनदेन की पारंपरिक जरूरतों को एक साथ जोड़ता है।

कलेक्टर्स किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती के लिये करें प्रोत्साहित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

उपज विक्रय के लिये किसानों को उपलब्ध कराएं मार्केट

मंडी में सोयाबीन की नीलामी पर रखें निगरानी, किसानों को दिलाएं भावान्तर का लाभ

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हमारा प्रदेश कृषि उपज पर आधारित है। इसलिए सरकार का मूल लक्ष्य प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना और कृषि फसलों की तुलना में उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ाना है। हमें इन क्षेत्रों में उद्यमिता के नए अवसर भी बनाने हैं। सभी कलेक्टर्स अपने-अपने जिलों में 100-100 किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही किसानों को उपज विक्रय के लिये मार्केट भी उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर को कृषि उपज मंडी में सोयाबीन फसल की नीलामी पर सघन निगरानी रखने और भावान्तर योजना से किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस-2025 के पहले सत्र 'कृषि एवं संबद्ध सेक्टर्स' को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे ग्रामीण युवा आने वाले समय में कृषि उद्यमी बनें, इसके लिए हमें मिल-जुलकर प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि खेती को जैविक खेती की ओर ले जाना एक बड़ी चुनौती है, पर हमें यह चुनौती भी पार करनी ही होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अन्न अर्थात मिलेट्स को प्रोत्साहन देकर इनकी उपज को लगातार बढ़ाना भी हमारा लक्ष्य है, हमें इस दिशा में भी ठोस प्रयास करने होंगे। किसानों को परंपरागत खेती से शिफ्ट कर उद्यानिकी, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन जैसे आमदनी बढ़ाने वाले कार्यों की ओर लेकर जाना है। प्रदेश में केला, संतरा, टमाटर एवं अन्य उद्यानिकी की फसलें बड़ी मात्रा में होती हैं। हमें इनके स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण एवं बड़े बाजारों तक मार्केटिंग की व्यवस्था भी करनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों में उर्वरक की खपत सिर्फ वैज्ञानिक आधार पर ही होनी चाहिए। यदि नहीं हो रही है तो इस पर नियंत्रण जरूरी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी कलेक्टर्स अपने-अपने जिलों में साप्ताहिक मार्केट, हाट बाज़ारों में प्राकृतिक एवं जैविक खेती की उपज का विक्रय सुनिश्चित करें। साथ ही किसानों को नकद फसलों की खेती के लिए समझाइश देकर प्रोत्साहित करें। इसके लिए अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर जिलों में किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित कर उसका रिकार्ड रखें और उनकी प्राकृतिक खेती के लाभों का अध्ययन भी करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों अर्थात् बागवानी को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने गुना जिले में गुलाब की खेती किए जाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि वहां के किसानों ने बड़ा ही प्रगतिशील कदम उठाया है। प्रदेश के सभी धार्मिक शहरों में भी गुलाब की खेती को बढ़ावा दिया जाये, जिससे गुलाब उत्पादन की खपत स्थानीय स्तर पर किया जा सके।

भावान्तर योजना का करें प्रचार-प्रसार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भावान्तर योजना का भी व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करें। इस योजना का सर्वाधिक लाभ किसानों को मिलना है और यह बात उन तक पहुंचनी भी चाहिए। भावान्तर योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिये सभी कलेक्टर पूरी मेहनत और समर्पण से किसानों को इसका अधिकतम लाभ दिलाएं।

पराली/नरवाई जलाने की घटनाओं पर लगाएं सख्त अंकुश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पराली पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में पराली/नरवाई जलाने की घटनाओं पर सख्ती से अंकुश लगाएं। इसके लिए सक्रिय नियंत्रण तंत्र विकसित करें और ऐसी घटनाओं पर विशेष फोकस कर निगरानी भी बढ़ाएं। कलेक्टर्स कृषि विभाग का सहयोग लेकर किसानों को पराली/नरवाई न जलाने की समझाइश दें। किसानों को पराली निष्पादन के दूसरे विकल्पों के बारे में बताया जाए, जिससे वे पराली जलाने की ओर प्रवृत्त ही न हों।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने दिया प्रेजेंटेशन

कृषि एवं संबद्ध सेक्टर्स सत्र का संचालन कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक वर्णवाल ने किया और प्रेजेंटेशन दिया। इस सत्र में प्राकृतिक खेती के प्रचार, जलवायु अनुकूल फसलों, उद्यानिकी फसलों के उत्पादन, उत्पादकता केंद्रित क्लस्टर, सूक्ष्म सिंचाई, मत्स्य पालन के लिए केज कल्चर और सेलेक्टिव ब्रीडिंग, फसल अवशेष प्रबंधन, खाद एवं बीज व्यवस्था, सोयाबीन के लिए भावांतर भुगतान योजना, दुग्ध उत्पादन और गौशाला प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री वर्णवाल ने फसल अवशेष प्रबंधन (पराली निष्पादन नियंत्रण) को सरकार की विशेष प्राथमिकता बताते हुए इस प्रयोजन के लिए कलेक्टर्स को गांव-गांव कृषक संगोष्ठियों के आयोजन और हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एवं बेलर जैसे उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने कहा कि जिलों में स्वीकृत कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। सत्र में रबी 2025-26 के लिए उर्वरक व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। सत्र में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं सहकारिता (मत्स्योद्योग) विभाग के सचिवों ने भी अपनी विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी।

पांच जिलों में हो रहा कृषि एवं उद्यानिकी पर बेहतरीन काम

सत्र में प्रदेश के 5 जिलों के कलेक्टर्स ने अपने-अपने जिलों में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों का उल्लेख किया। गुना कलेक्टर ने गुलाब क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में बताया। हरदा कलेक्टर ने प्राकृतिक एवं जैविक खेती के प्रोत्साहन किए गए प्रयासों की जानकारी दी। शाजापुर कलेक्टर ने खाद वितरण के लिए टोकन प्रणाली विकसित करने के बारे में बताया। श्योपुर कलेक्टर ने फसल अवशेष प्रबंधन (पराली निष्पादन नियंत्रण) की बेहतर व्यवस्था की जानकारी दी। खंडवा कलेक्टर ने जिले में सफलतापूर्वक गौशाला संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र के अंत में जिलों के कलेक्टर्स एवं कमिश्नर्स ने प्रदेश की कृषि उत्पादन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी दिए।

किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं सहित रबी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी स्वीकृति

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि को स्वीकृति देने का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर अन्नदाताओं का हित संवर्धन किया है। इस निर्णय से मध्यप्रदेश के किसान बंधु भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे। किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि तुलनात्मक रूप से देखें तो गत वर्ष की तुलना में गेहूं में 160 रूपए, जौ में 170 रूपए, चना में 225 रूपए, मसूर में 300 रूपए, रेपसीड और सरसो में 250 रूपए की वृद्धि की गई है। सर्वाधिक वृद्धि कुसुम के लिए 600 रूपए प्रति क्विंटल हुई है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 करने का निर्णय लिया है। इसी तरह जौ का समर्थन मूल्य 2150 रूपए, चना का 5875 रूपए, मसूर का 7000 रूपए, रेपसीड और सरसो का 6200 रूपए और कुसुम का 6540 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से बढ़ेगा दाल का उत्पादन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' की स्वीकृति का निर्णय भी किसान हित की दृष्टि से ऐतिहासिक है। वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक दाल उत्पादन 350 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 11 हजार 440 करोड़ रूपए का निवेश भी किया जाएगा। किसानों को दालों की नवीनतम किस्मों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा, इसके लिए 88 लाख नि:शुल्क बीज किट बांटे जाएंगे। फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की रणनीति भी बनाई गई है, लगभग एक हजार प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित होंगी। आने वाले 4 साल में किसानों से तुअर, उड़द और मसूर की सम्पूर्ण फसल की खरीद सुनिश्चित की जाएगी।

किसानों के चेहरों की मुस्कान ही हमारी असली दीवाली : मुख्यमंत्री

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की सेवा ही भगवान की सेवा है। बाढ़ हो, आपदा हो, ओलावृष्टि हो या कीट प्रकोप हो, किसान भाई हर विपदा से लड़ते और जूझते हैं। किसान पर कोई भी विपदा या आपदा आए सरकार संकट की हर घड़ी में साथी बनकर किसानों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से कहा कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा परिवार बनकर हम आपके साथ हैं। आपकी खुशी में ही प्रदेश की खुशी है। उन्होंने कहा कि हर प्रकार की आपदा और कीट प्रकोप से फसलों को हुई क्षति की राहत राशि किसानों को दी जाएगी। ये राहत राशि किसानों को बड़ा संबल देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जब तक आखिरी पीड़ित किसान को सहायता राशि नहीं मिल जाती, हमारी सरकार चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के चेहरों की मुस्कान ही हमारी असली दीवाली जैसी है। किसानों की मेहनत और जज्बां फिर से उनके खेतों को जीवन और समृद्धि से भर देगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में किसानों को प्राकृतिक आपदा और कीट प्रकोप से हुई फसल क्षति की राहत राशि

वितरण कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में बीते माहों में हुई अतिवृष्टि-बाढ़ और सोयाबीन में पीला मोजेक रोग से हुए फसल नुकसान के लिए 13 प्रभावित जिलों के 8 लाख 84 हजार 772 किसानों को 653.34 करोड़ की राहत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इसमें अतिवृष्टि/बाढ़ से हुई फसल क्षति से प्रभावित 3 लाख 90 हजार 167 किसानों को 331.34 करोड़ रूपये एवं पीला मोजेक/कीट व्याधि से हुई फसल क्षति से प्रभावित 4 लाख 94 हजार 605 किसानों को 322 करोड़ रुपये की राहत राशि शामिल है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

खोई मुस्कान लौटाना हमारी पहली प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी पीड़ित किसान भाईयों को राहत राशि देने और फसल सर्वे के कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। किसानों के चेहरे की खोई मुस्कान लौटाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 6 लाख 69 हजार से अधिक धान उत्पादक किसानों के खाते में 337 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया है। सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भी भावान्तर योजना शुरू की गई है। फसल के विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अन्तर की राशि सरकार सीधे किसानों को देगी। हम किसानों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों भाईयों के दुख-दर्द में हम आपके सेवक बनकर खड़े हैं। किसानों के माथे का पसीना बेकार नहीं जाएगा, आपकी मेहनत फिर से हरियाली का रूप लेकर प्रदेश को समृद्ध करेगी, हम सदैव आपके साथ हैं। राज्य सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है और उनके सुख-दु:ख में सहभागी है। हम प्रदेश के किसी भी किसान को आपदा में अकेला नहीं छोड़ेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2025-26 में अब तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को विभिन्न मदों में कुल 229 करोड़ 45 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। गत माह 6 सितंबर को ही फसल क्षति के लिए 11 जिलों के 17 हजार से अधिक किसानों को 20 करोड़ से अधिक की राहत राशि दी थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार द्वारा सोयाबीन में पीले मोजेक रोग से फसल प्रभावित किसानों को राहत राशि दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने किया किसानों से संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राहत राशि वितरण के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़ित किसानों से आत्मीय संवाद भी किया। संवाद के दौरान किसानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दशहरा एवं भव्य शस्त्र पूजन के आयोजनों एवं सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना लागू करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन किया। किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने दीपावली से पहले ही हमारी दीपावली मनवा दी। हमें यह महसूस हो रहा है कि सरकार हमारे साथ है। पीला मोजेक की राहत राशि हमें पहली बार मिली। यह सच्चे अर्थों में किसान हितैषी सरकार है। उत्साहित किसानों ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से राहत राशि मिलने से दशहरे पर ही किसानों की दीपावली हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुरहानपुर जिले के किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि केला आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राहत राशि मिलने पर सभी किसानों को बधाई देते हुए कहा कि आज से ही सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना के तहत पंजीयन प्रारंभ हो गया है। अब किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सोयाबीन मंडी में बेचें, यदि एमएसपी से कम राशि में फसल बिकती है, तो बेची गई फसल की कीमत और एमएसपी के अंतर की राशि यानि भावांतर की राशि अगले 15 दिनों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए किसानों को इस साल सोयाबीन का अत्यधिक भाव मिलेगा। इस बार सोयाबीन की एमएसपी 500 रुपए से अधिक बढ़कर 5328 रुपए हो गई है। केंद्र सरकार ने गेहूं की फसल के लिए फिर से एमएसपी बढ़ाई है। यह राज्य सरकार के किसानों की समृद्धि के संकल्प को पूरा करने की दिशा में लाभकारी रहेगा।

रतलाम जिले के किसानों को कुल 213.04 करोड़ रूपए की राहत राशि दी गई है। यहां के किसान श्री भरतलाल जाट और श्री प्रहलाद पाटीदार ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण उनकी सोयाबीन फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। उनके पास अगली फसल के लिए खाद और बीज खरीदने तक के लिए पैसा नहीं था लेकिन सरकार की राहत राशि मिलने से अब यह संकट खत्म हो गया है। जिले के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि आगामी 10 अक्टूबर को रतलाम में किसान सम्मेलन आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे स्वयं किसानों के बीच आयेंगे। नीमच जिले को अतिवृष्टि से सोयाबीन फसल को हुए नुकसान के लिए 119.06 करोड़ रूपए से अधिक की मुआवजा राशि दी गई। किसान श्री राकेश पाटीदार और श्री शंभुलाल अहीर ने कहा कि दशहरा और दीवाली के अवसर पर फसल की मुआवजा राशि मिलने से किसानों के सामने खाद-बीज खरीदने का संकट खत्म हो गया है। मंदसौर जिले के सोयाबीन उत्पादक किसानों को कुल 267.30 करोड़ रूपए राहत राशि अंतरित की गई है। यहां के किसान श्री लालदास बैरागी, श्रीमती रेखाबाई, श्री ओमप्रकाश, श्रीमती सुनीता शर्मा ने कहा कि मुआवजा राशि पाकर किसानों की दीपावली से पहले ही दीपावली मन गई है। उज्जैन जिले के किसानों को 44 लाख रूपए राहत राशि मिली है। किसान श्री पवन सिंह और श्री उदय सिंह ने कहा कि सरकार ने फसल कटने से पहले ही मुआवजा राशि दे दी है। भावांतर योजना में पंजीयन कराने के लिए यहां के किसान उत्साहित हैं। विदिशा जिले के किसानों को 62 लाख रूपए दिए गए हैं। किसान श्री भारत सिंह और श्री मनोज कुमार ने कहा कि भारी बारिश से फसल खराब हो गयी थी, सरकार ने मुआवजा देकर बड़ी मदद की है।

केला किसानों को प्रति हेक्टेयर 2 लाख की राहत राशि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बुरहानपुर जिले के केला उत्पादक अतिवृष्टि प्रभावित किसानों को 3.39 करोड़ रूपए मुआवजा राशि दी गई है। किसान श्री पांडुरंग बिट्टल और विनोद पुंडलिक ने कहा कि यहां के केला उत्पादक किसानों को लगभग 2 लाख प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जा रहा है और इससे बड़ी राहत हो गई है। शहडोल जिले के सोयाबीन उत्पादक पीला मोजेक प्रभावित 8935 किसानों को 6.36 करोड़ रूपए मुआवजा राशि मिली है। किसान श्री राजेन्द्र द्विवेदी और श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त किया। खंडवा जिले के सोयाबीन उत्पादक किसानों को अतिवृष्टि और पीला मोजेक की राहत के रूप में 55 लाख रूपए मिले हैं। किसान श्री कन्हैयालाल और श्री किशोर ने कहा कि आपदा में सरकार हमारा संबल बनी है। पीला मोजैक से हुए नुकसान की उन्हें पहली बार भरपाई की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खंडवा जिले में हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया। बड़वानी जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित 662 किसानों को 37 लाख रूपए मुआवजा राशि दी गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को दी 42 हजार करोड़ की ऐतिहासिक सौगात

फसल बीमा योजना ने किसानों को रुपये 1.83 लाख करोड़ से अधिक का मुआवजा प्रदान किया।

एफपीओ एवं नवाचारों में नई ऊंचाई

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि देशभर में 52 लाख किसान, एफपीओ के शेयर होल्डर बन चुके हैं, और 1,100 एफपीओ करोड़पति बनकर रुपये 15,000 करोड़ से अधिक का टर्नओवर दर्ज कर चुके हैं। इन संगठनों के लिए कृषि मंत्रालय निरंतर नवाचार और ब्रांडिंग समर्थन दे रहा है।

आत्मनिर्भरता, स्वदेशी तथा विकसित भारत का संकल्प

श्री शिवराज सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि में वैश्विक मानकों को लक्ष्य बनाते हुए देश को 'आत्मनिर्भर' और 'विकसित' भारत बनाने का संकल्प दोहराया, वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वदेशी अपनाने और प्रतिस्पर्धा की राह पर अग्रसर होने की अपील की। कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता, किसानों की आय एवं सशक्तिकरण हेतु योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे।

सहकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्यशाला - 'सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन और सूचना' से मजबूत होगा सहकारी क्षेत्र

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला सह समीक्षा बैठक का उद्घाटन किया

सहकारिता आंदोलन सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है

सहकारिता संस्थाएं कृषि और ऋण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवा, सेवाओं और मूल्य-श्रृंखला एकीकरण जैसे क्षेत्रों में भी विस्तार कर रही हैं

दो दिवसीय कार्यशाला में पैक्स संचालन के पूर्ण डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने, पैक्स कर्मचारियों और सदस्यों की डिजिटल क्षमता का निर्माण करने और पैक्स को कृषि इनपुट, ऋण, खरीद और भंडारण जैसी एकीकृत सेवाएँ प्रदान करने वाली वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया

सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना कार्यशाला के प्रमुख विषयों में से एक थी

कार्यशाला में सभी पंचायतों और गाँवों में दो लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया गया

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (आईवाईसी) के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रमों का सक्रिय रूप से आयोजन करना चाहिए

राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे समितियों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर सहकारी पुरस्कार बेंचमार्किंग मानदंड स्थापित करें

सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने राज्यों से अपने यहाँ सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 'सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन और सूचना' के विषय पर काम करने का आग्रह किया

दिल्ली | सहकारिता क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के बारे में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला और समीक्षा बैठक आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आयोजित की गई। सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधि, सचिव, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) और सहकारी क्षेत्र के प्रमुख हितधारक शामिल हुए। कार्यशाला का उद्घाटन सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने श्री पंकज कुमार बंसल, अपर सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तथा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया।

डॉ. भूटानी ने अपने मुख्य भाषण में सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सहकारी आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज सहकारिताएँ कृषि और ऋण जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर स्वास्थ्य सेवा, सेवाओं और मूल्य-श्रृंखला एकीकरण जैसे क्षेत्रों में भी फैल गई हैं। उन्होंने तकनीकी प्रगति को संस्थागत और मानव क्षमता विकास के साथ जोड़ने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सहकारी समितियाँ जन-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार रहें।

सहकारी क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने पर केंद्रित पैक्स, एआरडीबी और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण पर एक समर्पित कार्यशाला आयोजित की गई। चर्चाओं में पैक्स संचालन के पूर्ण डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने, पैक्स कर्मचारियों और सदस्यों की डिजिटल क्षमता का निर्माण करने और पैक्स को कृषि इनपुट, ऋण, खरीद और भंडारण जैसी एकीकृत सेवाएँ प्रदान करने वाली वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के प्रयासों का उल्लेख किया गया। नाबार्ड ने परियोजना के लिए सॉफ्टवेयर विकास, हार्डवेयर खरीद और क्षमता निर्माण सहायता पर भी अपडेट प्रस्तुत किए।

सत्र का एक अन्य प्रमुख विषय सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना थी। कार्यशाला में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसकी शुरुआत प्रायोगिक चरण के अंतर्गत 500 पैक्स से हुई और इसे देश भर में 29,000 पैक्स तक बढ़ाया गया। चर्चाओं में व्यवसाय विविधीकरण के माध्यम से गोदामों की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने, भूमि की उपलब्धता, सहकारी शक्ति और मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधार पर पैक्स का मानचित्रण करने और स्थायी संचालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करने पर प्रकाश डाला गया।

सत्र में सभी पंचायतों और गांवों में दो लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन तथा सुदृढ़ीकरण पर भी चर्चा हुई। इसमें नए सहकारी गठन के लिए संभावित जिलों और प्रखंडों की पहचान करने, व्यवसाय सक्रिता और विविधीकरण के माध्यम से मौजूदा समितियों को मजबूत करने और ग्रामीण आजीविका सृजन के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (आईवाईसी) और मीडिया जनसंपर्क पर एक समर्पित खंड भी शामिल था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (आईवाईसी-2025) के महत्व को रेखांकित किया और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से इसके अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से आयोजित करने का आग्रह किया। "एक पेड़ माँ के नाम" पौधारोपण अभियान जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए, राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे बेंचमार्किंग मापदंडों के अनुसार समितियों द्वारा की गई प्रगति पर सहकारी पुरस्कार स्थापित करें। जनसंपर्क के महत्व पर बल देते हुए, सत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए सोशल मीडिया हैंडल के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया गया।

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की कठिनाइयों के निवारण पर एक और सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी चर्चा के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया।

सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने पर दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला और समीक्षा बैठक के दूसरे दिन, सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक सत्र शुरू हुआ, जिसका विषय "व्यावसायिक विविधीकरण के माध्यम से पैक्स के क्षितिज का विस्तार" था। इसमें प्रमुख पहलों पर भी चर्चा हुई। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रस्तुतियाँ दीं और अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया।

कार्यशाला में आत्मनिर्भरता अभियान के अंतर्गत तीन राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियों: राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल), और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

मंत्रालय ने मार्च 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की, जिसमें 30 क्षेत्रों की 8.4 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ और 32 करोड़ सदस्य शामिल हैं। एनसीडी सहकारी गतिविधियों, वित्तीय प्रदर्शन, लेखा परीक्षा की स्थिति और बुनियादी ढाँचे पर विस्तृत डेटा प्रदान करता है।

कार्यशाला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इफको-टोकियो के प्रतिनिधि की उपस्थिति में बीमा क्षेत्र में सहकारी समितियों की भूमिका पर चर्चा थी।

कार्यशाला के अंतिम सत्र में, सीआरसीएस ने राज्यों को बहु-राज्य सहकारी समितियों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों के बारे में जानकारी दी और बेहतर समन्वय के लिए उनकी सहायता मांगी।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव ने अपने समापन भाषण में रचनात्मक विचार-विमर्श की प्रशंसा की और ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और डिजिटल परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में पैक्स और बहु-राज्य सहकारी समितियों की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने सहकारी समितियों के प्रभावी प्रशासन के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने, डिजिटल उपकरणों और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि का लाभ उठाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य को राज्य में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 'सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन और सूचना' के विषय पर काम करना चाहिए।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश भर में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए अपने डेटा को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के साथ साझा करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मंत्रालय बैंकिंग से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए पहले से ही काम कर रहा है। इसमें आय के अवसरों को बढ़ाने और स्थानीय उद्यमिता को मज़बूत करने के लिए सहकारी व्यवसायों के विविधीकरण को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन, वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता और सहकारी संसाधनों के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन के समापन में सचिव ने तिरुपति में कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार और सहकारिता विभागों को धन्यवाद दिया।

सत्र का समापन संयुक्त सचिव श्री रमन कुमार द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने राज्य के प्रतिनिधियों, केंद्रीय अधिकारियों और हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और बहुमूल्य योगदान के लिए उनके प्रयासों की प्रशंसा की।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ ने पैक्स प्रबंधकों को सशक्त बनाने के लिए दी सहकारी नीतियों की जानकारी"

नाबार्ड प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में पैक्स प्रबंधकों को सहकारी नीतियों की दी गई जानकारी

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के सहकारी प्रशिक्षण केंद्र में नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉव योजनान्तर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर, राजगढ़, सीहोर, देवास, नर्मदापुरम , रायसेन , बेतूल से संबंधित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के प्रबंधकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इन सभी कार्यशालाओं में कुल 262 पैक्स प्रबंधकों ने भाग लिया। नाबार्ड प्रायोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 03 अक्टूबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक किया गया, जिसमें कुल 6 सत्र आयोजित किए गए।

कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को राज्य एवं राष्ट्रीय सहकारी नीतियों के अनुरूप कार्य करते हुए किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सहकारिता के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों और ग्रामीण हितधारकों तक लाभ पहुँचाना सभी का दायित्व है।

राष्ट्रीय एवं राज्य सहकारी नीति

श्री पी. के. एस. परिहार, पूर्व महाप्रबंधक, अपेक्स बैंक ने राष्ट्रीय एवं राज्य सहकारी नीतियों की रूपरेखा और उद्देश्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सहकारी संस्थाएँ देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इनके माध्यम से किसानों, ग्रामीणों एवं लघु उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी नीति के प्रमुख बिंदुओं - पारदर्शिता, भागीदारी, जवाबदेही और आत्मनिर्भरता - पर विशेष जोर दिया तथा यह भी समझाया कि राज्य सहकारी नीति को केंद्र की नीति के अनुरूप क्रियान्वित करने से समितियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय सहकारी नीति

श्री कुमार जोशी, सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त, सहकारिता ने राष्ट्रीय सहकारी नीति के उद्देश्य, इसकी संरचना एवं सहकारी समितियों की भूमिका पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई सहकारी नीति का मुख्य उद्देश्य सहकारिता को एक जन-आंदोलन बनाना है, जिससे हर किसान और ग्रामीण व्यक्ति को आर्थिक अवसर प्राप्त हों। उन्होंने नीति के अंतर्गत सहकारी बैंकों, डेयरी समितियों, और बहुउद्देशीय समितियों को सशक्त करने के उपायों का भी उल्लेख किया।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी नीति

श्री प्रदीप निखरा, सेवानिवृत्त अपर संयुक्त आयुक्त, सहकारिता ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी नीति पर विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने राज्य स्तर पर चल रही सहकारी समितियों की संरचना, उद्देश्यों, शासन की प्राथमिकताओं और नई सुधारात्मक पहलों पर जानकारी दी। श्री निखरा ने बताया कि राज्य नीति में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि व्यवसायों के विस्तार, और ग्रामीण युवाओं को सहकारी ढाँचे से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने पैक्स प्रबंधकों को प्रेरित किया कि वे स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता और सदस्य सहभागिता को प्राथमिकता दें।

बहुउद्देशीय पैक्स की नवीन उपविधियों

अंतिम सत्र में पुनः श्री पी. के. एस. परिहार ने बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) की नवीन उपविधियों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि नई उपविधियों के तहत पैक्स को केवल ऋण प्रदाता संस्था न मानकर, एक बहुउद्देशीय इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है — जो कृषि विपणन, उर्वरक वितरण, बीज उत्पादन, पशुपालन और कृषि उपकरण किराए पर देने जैसी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाएगी। उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि इन सुधारों से पैक्स न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, बल्कि किसानों के जीवन स्तर में भी ठोस सुधार आएगा।

अंतिम सत्र में प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के समाधान महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह ने किए।प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों से फीडबैक लिए गए तथा सभी को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। विशेषज्ञों ने कहा कि पैक्स प्रबंधकों को सहकारी ढाँचे को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और किसानों की आमदनी में वृद्धि हो।

भोपाल में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ

देशभर की कला, संस्कृति और शिल्पकारों का अनूठा संगम

भोपाल। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा सीएचसीडीएस योजना के अंतर्गत भोपाल में आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। प्रदर्शनी 8 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर तक चलेगी।

इस अवसर पर संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ; नर सिंह सैनी, , सहायक निदेशक, हस्तशिल्प सेवा केंद्र भोपाल , जी.पी. मांझी, प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल तथा धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सचिव, विशेषज्ञ संस्था सीड सहित अनेक अधिकारी, शिल्प प्रेमी तथा देशभर से आए कारीगर उपस्थित रहे।

कला और संस्कृति का महोत्सव

इस प्रदर्शनी में देशभर के विभिन्न प्रांतों की समृद्ध हस्तशिल्प परंपराओं और लोककलाओं को एक मंच पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें सम्मिलित शिल्प और उत्पादों में शामिल हैं:

बनारस की विश्वप्रसिद्ध कतान सिल्क, मसलिन सिल्क, टीसू सिल्क, अल्फी और टिल्फी सिल्क,भागलपुर की सिल्क साड़ियाँ एवं सूट्स ,उज्जैन की बटिक प्रिंट ,दिल्ली की आकर्षक ज्वेलरी ,भोपाल की जरी-जरदोजी और जूट उत्पाद ,ग्वालियर व जबलपुर का वुड वर्क, पैच वर्क और स्टोन क्राफ्ट ,मधुबनी की विश्वप्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग ,प्रयागराज का ड्राई फ्लावर क्राफ्ट ,हैदराबाद की कलमकारी ,बुधनी के आकर्षक पारंपरिक खिलौने ,भदोही के हस्तनिर्मित कारपेट भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र हैं।

शिल्पकारों को प्रोत्साहन

यह प्रदर्शनी न केवल कला प्रेमियों और आम नागरिकों के लिए भारतीय हस्तशिल्प की विविधता को समझने का अवसर है, बल्कि इसमें भाग लेने वाले शिल्पकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने, विपणन के अवसर प्राप्त करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने का भी मंच प्राप्त हो रहा है।

प्रदर्शनी स्थल पर आगंतुकों को सीधे शिल्पकारों से उत्पाद खरीदने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे शिल्प के मूल स्वरूप को अनुभव करने के साथ-साथ पारंपरिक कारीगरों को सीधे समर्थन मिल रहा है।

कला प्रेमियों के लिए सुनहरा अवसर

भोपाल में आयोजित यह प्रदर्शनी देश के सांस्कृतिक वैभव की झलक प्रस्तुत करती है और शहरी नागरिकों को ग्रामीण एवं पारंपरिक शिल्पों से जोड़ती है। यह आयोजन न केवल कारीगरों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि भारत की विविध सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और संप्रेषित करने का सार्थक प्रयास भी है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।